www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 40 || लखनऊ
रविवार
10 मई 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा

दैनिक तमसा संकेत

https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:22
सूर्यास्तः 06:44
अधिकतमः 36°00
न्यूनतमः 26°00

पेज 03

विशेष समाचार | महिला आरक्षण पर राजनीतिक दलों... » पेज 02 | ट्रेन के इंजन पर चढ़ीं पल्लवी पटेल... » पेज 04 | उर्वशी ने विराट कोहली को बताया...

फास्ट न्यूज

अग्नि की एडवांस मिसाइल का सफल परीक्षण

भुवनेश्वर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने शुक्रवार को ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण सेंटर से अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेड री-एंट्री व्हीकल सिस्टम लगाया गया है, जिससे एक साथ कई परमाणु हथियारों को ले जाया जा सकता है। साथ ही एक बार में कई टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है।

देश में 70 साल में 20 लाख अपहरण

नई दिल्ली। भारत में अपहरण और जबरन उठा ले जाने की घटनाएं पिछले एक दशक में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। हाल ही में भोपाल में एक आईएएस एकेडमी की निदेशक के अपहरण और 1.89 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1953 से 2024 के बीच देश में कुल 20 लाख से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन सात दशकों के कुल मामलों का 54% हिस्सा (11.24 लाख केस) केवल पिछले 11 वर्षों (2013-2024) में दर्ज हुआ है।

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि नए सीडीएस होंगे

नई दिल्ली। रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। केंद्र ने शनिवार को इसका ऐलान किया। सुब्रमणि रक्षा मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। दोनों 31 मई को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा CDS अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को खत्म हो रहा है।

लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खेला बैडमिंटन

खेल मैदान अनुशासन, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पाठशाला : योगी

- सीएम योगी का प्रतीक चिह्न देकर स्वागत किया गया।
- सीएम योगी ने बैंड वालों को सम्मानित किया।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर (बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस) 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम बाबू बनारसी दास यू.पी. बैडमिंटन अकादमी में आयोजित किया गया।

» (शेष पेज 04 पर)

> मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "फिट इंडिया" विजन को उत्तर प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं समेत विभिन्न खेल आयोजनों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है।

खेल मैदान सबसे बड़ी पाठशाला : योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल मैदान वह स्थान है जहां अनुशासन का वह पाठ सीखने को मिलता है जो पुस्तकों में भी कठिन होता है।

खेल व्यक्ति को संकल्प, समर्पण और चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत में जितना अधिक पसीना बहता है, सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। खेल युवाओं को आपदा और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी देते हैं।

1400 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

सीएम योगी ने कहा कि पांच दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर से पुलिस और पैरामिलिट्री बलों के लगभग 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों का उत्तर प्रदेश की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क और मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है।

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल के बायो बदले

मुख्यमंत्री की जगह 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा का सीएम और टीएमसी फाउंडर लिखा

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार को सोशल मीडिया हैंडल के बायो बदल दिए। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और X के बायो में लिखा- 'फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और 15वीं, 16वीं, 17वीं विधानसभा की मुख्यमंत्री।' इससे पहले उनके बायो में फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, पश्चिम बंगाल लिखा था। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद ममता ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के इनकार कर दिया। ममता ने इस्तीफा नहीं दिया। 7 मई को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके बाद राज्यपाल आरएन रवि ने विधानसभा भंग कर दी थी 2021 में 17वीं विधानसभा का चुनाव जीतकर ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं थीं। वे 2011 से लगातार सत्ता में रहीं। हालांकि, अप्रैल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी को भी भवानीपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा।

2026 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा ने कुल 293 विधानसभा सीटों में से 207 सीटें जीतीं। जबकि तृणमूल 80 सीटों तक ही सिमट गई। बंगाल में भाजपा ने 293 में से 206 सीटें जीतकर करीब 70% का स्ट्राइक रेट हासिल किया।

ममता का फेसबुक प्रोफाइल अब :

ममता का एक्स हैंडल पहले :

विजय तमिलनाडु सीएम आज पद की शपथ ले सकते हैं

राज्यपाल को 121 एमएलए के समर्थन का लेटर दिया

तमसा संकेत, संवाददाता

चेन्नई। तमिलनाडु में TVK चीफ सी. जोसेफ विजय रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में दोपहर 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा।

विजय ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से लोकभवन में मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए 121 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी। 4 मई को आए चुनाव परिणाम में विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा 108 सीटें मिली थीं। लेकिन यह बहुमत से 10 कम थीं।

TVK को कांग्रेस के 5, CPI और CPI(M) के 2-2 विधायकों का समर्थन 8 मई तक मिल चुका था।

शनिवार को VCK और IUML ने TVK को अपने 2-2 विधायकों का समर्थन दिया। इधर, महाबलीपुरम स्थित फोर पॉइंट्स रिसॉर्ट के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। यहां TVK के सभी विधायक ठहरे हुए हैं। तमिलनाडु में सरकार बनने का रास्ता साफ होते ही, टीवीके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। TVK के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़े।

निरीक्षण : डीएम-एसपी ने मस्जिद और ईदगाह का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाएं परखी

त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। आगामी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। शनिवार को जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने थाना अलीगंज क्षेत्र के तलवापार और हंस तिराहा स्थित मस्जिद एवं ईदगाह का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी ली। दोनों अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की सक्रिय मौजूदगी

सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए और गश्त बढ़ाई जाए। उन्होंने त्योहारों के दौरान लोगों से सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाए रखने की अपील भी की।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए जरूरी निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्योहारों के दौरान साफ-सफाई, यातायात और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था बेहतर रखी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।

मस्जिद और ईदगाह परिसर का लिया जायजा

प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि त्योहारों के दौरान किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा

निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने के साथ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की।

> निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मस्जिद और ईदगाह परिसर का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। प्रवेश और निकास मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था तथा भीड़ नियंत्रण से जुड़े बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए।

सुवेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री

दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टूडू, निषिथ प्रमाणिक मंत्री बने, बांग्ला में शपथ ली

सुवेंदु राज

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। सुवेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में BJP के पहले मुख्यमंत्री बन गए। सुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को झुककर प्रणाम किया। सुवेंदु के साथ 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टूडू और निषिथ प्रमाणिक शामिल रहे।

कार्यक्रम में PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। NDA और BJP शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे। PM रोड शो करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे, मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धाजंलि दी। इसके बाद वे भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और पैर छुए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से घुटनों के बल झुककर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। .

पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने जोरासांको ठाकुरबाड़ी में श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया के सामने एक गीत गाया। जैसे ही सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, उनके पिता शिशिर कुमार अधिकारी ने कहा, ₹हमने नंदीग्राम की लड़ाई लड़ी और उस संघर्ष की अगुआई सुवेंदु ने की थी। बार-बार, अलग-अलग तरीकों से उन्हें पीछे धकेलने की कोशिशें की गईं, लेकिन आज आम लोगों को भी जीत मिली है। यह सिर्फ नंदीग्राम की बात नहीं है। » (शेष पेज 04 पर)

माखनलाल सरकार 82 साल से आरएसएस से जुड़े

पीएम मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ समारोह में 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार से मुलाकात की। मोदी ने मंच पर पहुंचते ही माखनलाल को गले लगाया, अभिवादन किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। माखनलाल बंगाल के सबसे बुजुर्ग भाजपा कार्यकर्ता हैं। 74 साल पहले 1952 में वे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराने के आंदोलन में भी शामिल हुए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। माखनलाल सरकार 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवर संघ (RSS) में शामिल हुए थे। वे 82 साल से RSS के कार्यकर्ता हैं। वे आजादी के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन में भी शामिल रहे।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने सुवेंदु को सीएम बनने पर बधाई दी

बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने पर सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी। शेख हसीना, फिल्हाल भारत में ही शरण लिए हुए हैं।

सिलीगुड़ी में भाजपा को खड़ा किया, एक साल में 10 हजार नए सदस्यों को जोड़ा

- भाजपा के गठन के बाद 1980 में माखनलाल सरकार को पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों का संगठनात्मक समन्वयक बनाया गया। वे संगठन की सिलीगुड़ी जिला शाखा के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी में गो-हत्या बंद कराई।
- 1981 से लगातार सात साल तक वे जिला अध्यक्ष रहे। उस दौर में किसी नेता का लंबे समय तक एक ही संगठनात्मक पद पर बने रहना बड़ी उपलब्धि माना जाता था।
- एक साल में 10 हजार नए सदस्यों को संगठन से जोड़ा। सिलीगुड़ी सीट पर उन्होंने ही शंकर घोष की उम्मीदवारी का फैसला किया था। वे कहते हैं- अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सिलीगुड़ी में भाजपा की जीत संभव नहीं थी।
- भाजपा आज जिस "बंगाल निर्माण" की बात करती है, उस सपने को माखनलाल सरकार ने दशकों पहले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर देखा था।

गडकरी बोले- बंगाल में बीजेपी की विचारधारा को पहचान मिली; विकास होगा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को नागपुर में कहा कि पश्चिम बंगाल में BJP की शानदार जीत दिखाती है कि पार्टी की विचारधारा को अब वहां के लोगों के बीच पहचान मिल गई है।राज्य में सत्ता परिवर्तन बंगाल के विकास का रास्ता बनाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में शामिल होने से पहले एजेंसी से बात कर रहे थे। BJP ने हाल ही में हुए चुनावों में 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 207 सीटें हासिल कीं, जिससे तृणमूल कांग्रेस (TMC) का 15 साल का शासन खत्म हो गया और पूर्वी भारत में उसकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी लिखी। भवानीपुर विधानसभा सीट पर TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराने वाले सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

कांथी में सुवेंदु के पड़ोस में रहने वाले शख्स ने कहा- शुरू से ही, सुवेंदु अधिकारी हमेशा अपने साथियों और दोस्तों के साथ एकजुट होकर खड़े रहे हैं, और हमेशा मदद के लिए तैयार रहे हैं। सुवेंदु अधिकारी में यह खूबी है कि वे कभी अपना अतीत नहीं भूलते और हमेशा प्यार से मदद करते हैं।

शपथ के बाद एयरपोर्ट पर 7 राज्यों के सीएम, विक्ट्री साइन दिखाया

शपथ के बाद हरियाणा CM नायब सैनी, बिहार CM सम्राट चौधरी, उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली CM रेखा गुप्ता, सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल के CM पेमा खांडू और मेघालय CM कॉनराड संगमा ने एयरपोर्ट पर नजर आए। उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया।

चुनावी हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार से मिले पीएम

शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के दिवंगत कार्यकर्ताओं देबाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल के परिवारों से मुलाकात की।

दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट

इंटेलिजेंस बोली- गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है

- दिल्ली में भाजपा मुख्यालय और आसपास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के आधार पर यह जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक, भाजपा मुख्यालय और आसपास की सरकारी इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एजेंसियों को शक है कि दीन दयाल उपाध्याय (DDU) मार्ग स्थित कार्यालयों को आत्मघाती हमलों,

कार ब्लास्ट, गोलीबारी या IED के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। किसी भी खतरे को टालने के लिए सुरक्षा बलों ने निगरानी और एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती, चेकिंग और सीसीटीवी निगरानी बढ़ा दी है।

» (शेष पेज 04 पर)

पंजाब के आप मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार

ईडी टीम अरोड़ा को चंडीगढ़ से दिल्ली ले गई

पूछताछ

तमसा संकेत, एजेंसी

वेद/मुनीष, चंडीगढ़/लुधियाना। केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह हुई रेड के वक्त वह चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अपनी सरकारी कोठी पर ही थे।<

इसके बाद करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई। जिसके बाद शाम करीब 5 बजे ED की टीम चंडीगढ़ और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में उन्हें दिल्ली ले गई। आगे की पूछताछ उनसे दिल्ली में ही होगी।

उनकी रात ED के लॉकअप में बीतेगी। ED ने शनिवार सुबह ही मंत्री अरोड़ा पर रेड चंडीगढ़ में उनके सरकारी घर, दिल्ली और गुरुग्राम के 5 ठिकानों में हुई है। ED ने खुलासा किया कि अरोड़ा ने अपनी फर्मों के जरिए मोबाइल खरीद की करीब 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी एक्सपोर्ट किए।

» (शेष पेज 04 पर)

सम्पादकीय

तमिलनाडु में सत्ता का बेवजह विवाद

हाल में संपन्न चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत के बाद एक जबरदस्त कटाक्ष सोशल मीडिया पर पढ़ने मिला कि ये तो मोदीजी का बड़प्पन है कि चुनाव करवाने के बाद भाजपा को विजेता दिखाते हैं। वाकई देश में एक अजब मुकाम पर आ पहुंचा है कि जहां चुनाव से पहले ही ऐलान हो जाता है कि आएगा तो मोदी ही और इस घोर अलोकतांत्रिक रवैये पर अब जनता ने सवाल उठाना भी छोड़ दिया है। जब पहले से तय है कि आएगा तो मोदी ही, तो उसके बाद भी चुनाव की लंबी-चौड़ी, खर्चीली प्रक्रिया की औपचारिकता निभाना वाकई बड़प्पन ही है। कम से कम लोकतांत्रिक, निष्पक्ष चुनाव का भरम तो बना ही हुआ है। इसी भरम के सहारे भाजपा या चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी मिलता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो कहीं-कहीं कांग्रेस या दूसरे दलों को जीत कैसे मिलती है। यानी एकाध जगह अगर भाजपा के खिलाफ कोई जीत गया तो उसे ही चुनाव आयोग और भाजपा की निष्पक्षता के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन विपक्ष के जीते हुए राज्यों में भी भाजपा किस तरह खेल करती है, इसका ताजा उदाहरण तमिलनाडु से सामने आ रहा है। इस बार तमिलनाडु में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 243 सीटों की विधानसभा के चुनाव में टीवीके ने कुल 108 सीटें हासिल की है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 का है। कांग्रेस ने 5 सीटों के साथ टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया है, फिर भी बहुमत के लिए जरा सी कसर बाकी है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की नौबत पहली बार किसी राज्य में हुई हो, जिस पर फैसला लेने में वक्त लग रहा हो। त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा की स्थिति कई बार बनी है। लेकिन आम तौर पर इसमें सबसे बड़ा दल ही सरकार बनाने का दावा पेश करता है और राज्यपाल उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। तमिलनाडु में भी टीवीके नेता विजय ने बुधवार को तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन तब राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया और कहा कि स्थिर सरकार के लिए जरूरी है कि आप बहुमत दिखाने के लिए साथ देने वाले विधायकों के हस्ताक्षर लेकर आएं। अब इतनी जल्दी तो हस्ताक्षर जुटाए नहीं जा सकते, लिहाजा विजय गुरुवार को भी राज्यपाल के पास पहुंचे और करीब 45 मिनट की मुलाकात में फिर सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए भरोसा दिलाया कि वे बहुमत साबित कर लेंगे। लेकिन उन्हें दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह राज्यपाल श्री अर्लेकर ने कहा कि पहले विधायकों के साइन लेकर आओ। जबकि यह राज्यपाल का काम नहीं है कि वह सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी से बहुमत साबित करने कहे, यह काम विधानसभा फ्लोर टेस्ट में होता है। अगर विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बहुमत साबित नहीं कर पाते, तब तो उन्हें सत्ता पर बैठने का हक नहीं है। लेकिन उससे पहले ही उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करके एक गलत मिसाल पेश की जा रही है। बीच कई किस्म के कयास लगने शुरु गए, जैसे एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे, या विजय को एआईएडीएमके के कुछ विधायक भी समर्थन दे सकते हैं, आदि, आदि। दरअसल एआईएडीएमके के कई विधायकों को पुडुचेरी के एक निजी होटल में ठहराया गया है। खबरों के मुताबिक एआईएडी-एम के एक गुट का मानना है कि पार्टी को टीवीके का समर्थन करना चाहिए, जबकि दूसरा गुट इसके $िखलाफ़ है। इस मुद्दे पर पार्टी के महासचिव ईके पलानीस्वामी की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई। हालांकि, एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री केपी मुनुस्वामी ने कहा है कि टीवीके को एआईएडीएमके का समर्थन मिलने की ख़बर झूठी है। वहीं डीएमके ने भी कहा है कि वह सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने साफ शब्दों में कहा है कि विजय को सरकार बनाने दी जाए। स्टालिन ने कहा कि डीएमके अगले छह महीने तक बिना किसी हस्तक्षेप के नयी सरकार को देखेगी और उसके बाद कोई फैसला लेगी। स्टालिन ने संकेत दिया कि फिलहाल डीएमके राज्य में ना तो संवैधानिक संकट चाहती है और ना ही जल्द दोबारा चुनाव। उन्होंने कहा कि नई सरकार को उनकी सरकार की शुरू की गई योजनाओं को जारी रखना चाहिए और टीवीके के चुनावी वादों को भी पूरा करना चाहिए। एम के स्टालिन ने विजय को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह कर एक नैतिक साहस दिखाया है। जो संघ से दीक्षित राज्यपाल अर्लेकर नहीं दिखा पा रहे हैं। दरअसल उन्हें केवल संविधान के अनुसार चलना है, लेकिन भाजपा के विरोधी दलों को सत्ता से दूर रखने के लिए वे यह भी नहीं कर पा रहे हैं। Mइस मामले पर अब तमिलनाडु में सियासत तेज हो गई है। डीएमके के साथ गठबंधन में रही कांग्रेस ने टीवीके का साथ तो दिया ही है, बाकी दल भी जो टीवीके के साथ नहीं हैं, वे भी राज्यपाल पर सवाल उठा रहे हैं। माकपा महासचिव एम.ए. बेबी ने कहा है कि 'टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल विजय को अपना दावा पेश करने के लिए क्यों नहीं बुला रहे हैं?

महिला आरक्षण पर राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र

> राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि महिला सशक्तीकरण केवल भाषणों और घोषणाओं से नहीं आएगा, बल्कि वास्तविक प्रतिनिधित्व और समान अवसरों से आएगा। कथनी और करनी के इस अंतर को समाप्त किए बिना महिला आरक्षण का सपना अधूरा ही रहेगा।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यह है कि जिस देश में महिलाओं को "शक्ति", "मातृशक्ति" और "आधी दुनिया" कहकर सम्मानित किया जाता है, वहीं राजनीति में उन्हें समान भागीदारी देने के प्रश्न पर लगभग सभी राजनीतिक दलों की नीयत संदिग्ध दिखाई देती है। संसद से लेकर चुनावी मंचों तक महिला आरक्षण के समर्थन में बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब उम्मीदवारों को टिकट देने का समय आता है, तब अधिकांश दल महिलाओं को हाशिये पर धकेल देते हैं। हालिया विधानसभा चुनावों ने इस विरोधाभास को एक बार फिर उजागर कर दिया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को दिए गए टिकटों का आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि महिला प्रतिनिधित्व को लेकर दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संसद में जोरदार राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला, लेकिन उन्हीं दलों ने चुनावी मैदान में महिलाओं को पर्याप्त अवसर देने में उत्साह नहीं दिखाया। यह केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नैतिकता का भी प्रश्न है। सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल चुनाव की रही। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सीटों में से केवल लगभग 33 महिलाओं को टिकट दिए, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर करीब 52 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। यह संख्या कुल टिकटों का लगभग दस प्रतिशत ही बैठती है। तमिलनाडु में भी स्थिति बहुत अलग नहीं रही। सत्ता परिवर्तन के दावे करने वाले दलों ने महिलाओं को सीमित अवसर दिए। असम और केरल जैसे राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने महिलाओं को प्रतीकात्मक उपस्थिति से आगे नहीं बढ़ने दिया। परिणाम यह हुआ कि कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या अत्यंत कम रही। यह स्थिति तब है, जब देश की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं। दरअसल भारतीय राजनीति लंबे समय से पुरुष प्रधान मानसिकता से संचालित होती रही है।

राजनीतिक दल महिलाओं को अक्सर "सुरक्षित" या "कमजोर" उम्मीदवार मानते हैं। उन्हें यह भय रहता है कि महिला प्रत्याशी चुनावी संघर्ष, धनबल, बाहुबल और जातीय समीकरणों के बीच प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। यही कारण है कि अधिकांश दल महिलाओं को उन्हीं सीटों पर टिकट देते हैं जहां उनकी जीत की संभावना कम होती है या जहां केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति दर्ज करानी होती है। विडंबना यह भी है कि जो राजनीतिक दल संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में जोरदार भाषण देते हैं, वे अपने संगठनात्मक ढांचे में भी महिलाओं को निर्णायक स्थान देने से बचते हैं। अधिकांश राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व पर पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाओं को प्रायः महिला मोर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम या सामाजिक अभियानों तक सीमित कर दिया जाता है। निर्णय लेने वाली समितियों और रणनीतिक पदों पर उनकी भागीदारी बेहद कम दिखाई देती है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया था। विपक्ष पर महिलाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। लेकिन सवाल यह है कि यदि वास्तव में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को लेकर गंभीर इच्छाशक्ति होती, तो बिना किसी संवैधानिक बाध्यता के भी दल अपने स्तर पर अधिक महिलाओं को टिकट दे सकते थे। आखिर किसने रोका था कि भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक या अन्य दल कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को उम्मीदवार बनाते? स्पष्ट है कि महिला आरक्षण का मुद्दा कई बार वास्तविक सामाजिक प्रतिबद्धता से अधिक राजनीतिक लाभ का माध्यम बन जाता है।

हालांकि यह भी स्वीकार करना होगा कि राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील और मानवीय बना सकती है। विश्व के अनेक देशों के अनुभव बताते हैं कि जहां महिलाओं की राजनीतिक उपस्थिति बढ़ी है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण, बाल सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता मिली है। भारत में पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अनेक महिला सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है। महिलाओं की उपस्थिति केवल संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि दृष्टिकोण का भी प्रश्न है। महिलाएं समाज के उन अनुभवों और समस्याओं को सामने लाती हैं, जिन्हें पुरुष प्रधान राजनीति अक्सर नजरअंदाज कर देती है। घरेलू हिंसा, मातृत्व स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षा, बालिका शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को मजबूती तभी मिलती है, जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो। लेकिन दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनकी चर्चा आवश्यक है। कई बार राजनीतिक दल केवल औपचारिकता निभाने के लिए महिलाओं को टिकट देते हैं। ऐसे मामलों में वास्तविक सत्ता उनके परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथ में रहती है। पंचायतों में "सरपंच पति" जैसी प्रवृत्तियां इसका उदाहरण हैं। राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद के कारण भी कई योग्य महिलाएं अवसर से वंचित रह जाती हैं, जबकि राजनीतिक परिवारों से जुड़ी महिलाओं को अपेक्षाकृत आसान प्रवेश मिल जाता है। इसलिए केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता का विकास भी आवश्यक है। एक अन्य चुनौती चुनावी राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण और अत्यधिक खर्च है। भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ना अत्यंत महंगा और संघर्षपूर्ण हो गया है। धनबल और बाहुबल की संस्कृति महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है। सामाजिक रूढ़ियां भी बड़ी बाधा हैं। आज भी अनेक परिवार राजनीति को महिलाओं के लिए "उपयुक्त क्षेत्र" नहीं मानते। देर रात की राजनीतिक गतिविधियां, सार्वजनिक आलोचना और चरित्र हनन की आशंकाएं भी महिलाओं को राजनीति से दूर करती हैं। सवाल यह भी है कि क्या केवल आरक्षण से समस्या हल हो जाएगी? संभवतः नहीं। आरक्षण एक आवश्यक शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसके साथ सामाजिक सोच में परिवर्तन भी जरूरी है। राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को निर्णायक भूमिका देनी होगी।

■ ललित गर्ग

इसलिए पार्टी अब...

अशोक भाटिया

भारी विरोध के बावजूद भाजपा कैसे जीतेगी पंजाब में ?

पं. बंगाल, असम, पुडुचेरी में भारी जीत के बाद भाजपा के हौंसले बुलंद है और जीत का झंडा पंजाब में लहराने का मन बना रही भाजपा के लिए पंजाब टेढ़ी खीर से कम नहीं। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भाजपा पंजाब का किला भेदने की हर कोशिश में जुटी है लेकिन क्या भाजपा से नाराज चल रहा पंजाब का एक बड़ा गुट,पार्टी को माफ करेगा,क्या इस बार बंगाल की तरह भाजपा पंजाब में भी कमल खिलाएगी ? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा के रणनीति का शिकार होंगे ? सवाल कई है दरअसल इस समय भाजपा नेतृत्व इसे अगले संभावित "डोमिनो" के रूप में देख रहा है—ऐसा राज्य जहां राजनीतिक अस्थिरता और विपक्षी दलों की कमजोरी उसे नई संभावनाएं दे सकती है। इसी सोच के तहत भाजपा ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि वह 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, यानी किसी क्षेत्रीय सहयोगी के सहारे नहीं। डोमिनो प्रभाव एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया है, जहां एक घटना या क्रिया अपने समान अन्य घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देती है, ठीक वैसे ही जैसे एक के बाद एक रखे गए डोमिनो टाइल्स के गिरने से पूरी कतार गिर जाती है। यह अवधारणा बताती है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव या शुरुआती घटना बहुत बड़े और व्यापक परिणाम पैदा कर सकती है। वैसे देखा जाय तो पंजाब में भाजपा की मौजूदगी नई नहीं है। आज़ादी के बाद से ही पार्टी (और उससे पहले भारतीय जनसंघ) राज्य की राजनीति में सक्रिय रही है। लेकिन लंबे समय तक उसका प्रभाव मुख्यतः शहरी हिंदू वोटरों और व्यापारिक वर्ग तक सीमित रहा।1992 से पहले जब भाजपा अकेले चुनाव लड़ती थी, तब उसका औसत वोट शेयर लगभग 6-7% के बीच रहता था। 1997 में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन के बाद यह बढ़कर लगभग 8% तक पहुंचा।हालांकि गठबंधन ने भाजपा को सत्ता में भागीदारी तो दी, लेकिन उसका राजनीतिक विस्तार सीमित ही रहा। अकाली दल 94 सीटों पर चुनाव लड़ता था जबकि भाजपा के हिस्से केवल 23 सीटें आती थीं। भाजपा के कई नेताओं का मानना था कि इस "जूनियर पार्टनर मॉडल" ने पार्टी को पंजाब में स्वतंत्र पहचान बनाने से रोक दिया 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ हुए व्यापक आंदोलन ने पंजाब की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। किसानों के तीखे विरोध के बीच अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यही वह मोड़ था जिसने भाजपा को पंजाब में "नई शुरुआत" का अवसर दिया। गठबंधन टूटने के बाद भाजपा अब अपने संगठनात्मक विस्तार और नए सामाजिक समीकरणों पर खुलकर काम कर पा रही है।इसी वर्ष मार्च में अमित शाह ने मोगा की "बदलाव रैली" में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत देकर स्पष्ट कर दिया कि भाजपा अब पंजाब में सहायक दल नहीं, बल्कि मुख्य शक्ति बनने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा की रणनीति केवल संगठन विस्तार तक सीमित नहीं है। पार्टी यह भी मान रही है कि पंजाब की मौजूदा राजनीति में एक "राजनीतिक खालीपन" बन रहा है। आम आदमी पार्टी 2022 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसे आंतरिक असंतोष और नेतृत्व संबंधी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगे व्यक्तिगत आरोपों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का अवसर दिया है।हालांकि AAP अब भी पंजाब में एक मजबूत शक्ति है, लेकिन भाजपा यह मानती है कि शहरी वर्ग और गैर-पारंपरिक मतदाता धीरे-धीरे विकल्प तलाश सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पंजाब में लंबे समय से आंतरिक खींचतान से जूझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दलित प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाना और राहुल गांधी का राज्य इकाई को "टीम की तरह काम करने" की सलाह देना इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर असहमति बनी हुई है। कभी पंजाब की राजनीति का सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय दल माना जाने वाला अकाली दल भी अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। कृषि कानूनों के मुद्दे और लगातार चुनावी झटकों ने उसके जनाधार को कमजोर किया है। भाजपा को लगता है कि अकाली दल के कमजोर होने से जो राजनीतिक स्पेस खाली हुआ है, उसे वह भर सकती है। पंजाब में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राज्य की राजनीति परंपरागत रूप से सिख-पंथक और क्षेत्रीय मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इसलिए पार्टी अब "सोशल इंजीनियरिंग" मॉडल पर काम कर रही है।राज्य में अनुसूचित जाति (SC) आबादी लगभग 32% है, जो देश में सबसे अधिक अनुपातों में से एक है। इसके अलावा 25-30% आबादी ओबीसी वर्ग से जुड़ी मानी जाती है। भाजपा अब इन वर्गों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पार्टी सिख समुदाय के बीच केंद्र सरकार की पहलों—जैसे करतारपुर कॉरिडोर और साहिबजादों की शहादत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान—को प्रमुखता से प्रचारित कर रही है।राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा पंजाब में "हिंदू बनाम सिख" की पारंपरिक रेखा से आगे जाकर नया सामाजिक गठबंधन बनाना चाहती है।भाजपा की रणनीति इस विचार पर आधारित दिखती है कि यदि वह लगातार नए राज्यों में अपनी मौजूदगी स्थापित करती रही, तो इससे "मनोवैज्ञानिक विस्तार" का प्रभाव पैदा होगा।

बड़े पैमाने पर...

डॉ.परकाला प्रभाकर

चुनावी नतीजों से अधिक महत्वपूर्ण हैं हटाए गए मतदाता

भारत में विपक्षी दल या तो भोले हैं या फिर हमें इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि 'वोट चोरी' का नारा लगाते समय वास्तव में वे ईमानदार नहीं हैं। अगर वे वाकई 'वोट चोरी' और बड़े पैमाने पर लक्षित मतदाता सूची से नाम हटाने की बात पर यकीन करते हैं तो वे इन फर्जी चुनावों में हिस्सा क्यों ले रहे हैं और उन विधानसभाओं में क्यों बैठे हैं जिनका चुनाव 'वोट चोरी' और मतदाता सूची से नाम हटाने के आधार पर हुआ है? यह तर्क उचित है कि चुनावों में निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया पर उठ रहे गंभीर सवालों के मद्देनजर पूरे विपक्ष को चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए और लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे जनता की नजरों में भाजपा की वैधता खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी के रुख के बारे में बात करें। अगर वे वाकई घोषित जनादेश को अस्वीकार करने को लेकर गंभीर हैं और इस्तीफा देने से इंकार करती हैं तो इसका मतलब है कि वे नवगठित विधानसभा को मान्यता नहीं देतीं जिसका सीधा मतलब है कि वे निवर्तमान विधानसभा को अभी भी वैध मानती हैं। ऐसे में उन्हें यह कहना चाहिए कि इस अवैध चुनाव में चुने गए उनके दल के सभी लोग सदन से इस्तीफा दे दें और उनका इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। तब ममता का दावा मजबूत लगेगा। अगर आप कहें कि 'मेरी पार्टी के विजेता ठीक हैं लेकिन आपकी पार्टी के विजेता अवैध रूप से चुने गए हैं', तो इससे उनके इस दावे के बारे में क्या पता चलता है? अगर वे जीत भी जातीं तो भी नतीजों को अस्वीकार करना ही सही तर्क होता क्योंकि चाहे कोई भी जीता हो या हारा हो, 93 लाख वोटों को रद्द करना और 27 लाख लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करना पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ देता है। अगर यही उनका रुख होता तो इसे वास्तविक माना जाता और उनके इस रुख को पूरे भरोसे के साथ लिया गया कदम समझा जाता। दुर्भाग्य से अब उन पर हार को स्वीकार न करने का आरोप लग सकता है। बड़े पैमाने पर वोटों को रद्द किए जाने और 'विचाराधीन श्रेणी' के मतदाताओं की बड़ी तादाद को वोट डालने से रोके जाने के बाद अब समय आ गया है कि सभी विपक्षी दल एक साथ बैठें और गंभीरता से विचार करें। बिहार और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई 'वोट अधिकार' यात्रा पर विचार करें। इस यात्रा को 'हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र अधिकार 'मतदान के अधिकार की रक्षा' के लिए एक सामूहिक लड़ाई' के रूप में वर्णित किया गया था। इस यात्रा ने 1,300 किलोमीटर से अधिक की दूरी और 20 से अधिक जिलों को कवर किया जिसका उद्देश्य 'मतदाता सूची में हेरा-फेरी को उजागर करना और चुनाव आयोग से त्रुटिरहित मतदाता सूचियों की मांग करना' था। उमड़ती भीड़ को देखकर कांग्रेस को लगा कि वे किसी तरह जीत जाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि वंचित लोगों के बजाय चुनाव में जीत ज़्यादा मायने रखती थी। यदि वे जीत जाते तो क्या इसका मतलब यह होता कि नाम मिटाना और मताधिकार से वंचित करना मायने नहीं रखता? मतदान का अधिकार रखने वाले किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट जाना मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

जरा हटके

गांव स्तर पर कृषि...

अमरपाल सिंह वर्मा

राजस्थान में गेहूं की खेती महंगा सौदा क्यों?

राजस्थान में गेहूं पैदा करना अब किसानों के लिए लगातार महंगा सौदा बन गया है। हालात ऐसे हैं कि एक तरफ खेती की लागत तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ किसानों की बचत उसी अनुपात में नहीं बढ़ पा रही। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के विपणन अनुमान 2025 के आंकड़ों से इस समस्या की गंभीरता साफ दिखाई देती है। बड़ा सवाल है कि निरंतर बढ़ती लागत को किसान कैसे और कब तक झेल पाएंगे? आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में एक क्विंटल गेहूं पैदा करने की लागत करीब 1488 रुपये तक पहुंच चुकी है। वहीं पंजाब में यही लागत लगभग 905 रुपये है, यानी राजस्थान का किसान पंजाब के किसान की तुलना में करीब 64 प्रतिशत ज्यादा खर्च करके गेहूं उगा रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं है बल्कि उन मुश्किल परिस्थितियों की हकीकत है जिसे झेल कर राजस्थान का किसान खेती कर रहा है। देश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सभी राज्यों के लिए एक समान तय किया जाता है। इस साल गेहूं का एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। सुनने में यह व्यवस्था बराबरी वाली लगती है लेकिन समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि खेती की लागत हर राज्य में अलग-अलग है। पंजाब और हरियाणा में बेहतर सिंचाई व्यवस्था, मजबूत कृषि ढांचा और ज्यादा उत्पादन होने के कारण किसानों की लागत अपेक्षाकृत कम रहती है। वहीं राजस्थान का किसान कम पानी, महंगी सिंचाई और बढ़ती मजदूरी के बीच खेती करने को मजबूर है। ऐसे में समान एमएसपी होने के बावजूद उसकी वास्तविक बचत काफी कम रह जाती है। राजस्थान में पानी की कमी खेती की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रदेश के कई इलाकों में किसान पूरी तरह ट्यूबवेल और भूमिगत जल पर निर्भर हैं। भूजल लगातार नीचे जा रहा है और सिंचाई के लिए बिजली तथा डीजल पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। गेहूं को समय पर और कई बार सिंचाई चाहिए, बिजली और डीजल के खर्च के कारण यह सिंचाई स्वाभाविक रूप से यहां ज्यादा महंगी पड़ती है। इसके मुकाबले पंजाब में वर्षों से नहरों और भूजल आधारित सिंचाई का मजबूत नेटवर्क किसानों को राहत देता रहा है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के ज्यादातर इलाकों में नहरों का जाल बिछा हुआ है लेकिन यहां भी फसलों की जरूरत के समय नहर बंदी समस्या पैदा करती है। खेती की लागत बढने में मजदूरी भी बड़ा कारण बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में कृषि मजदूरी तेजी से बढ़ी है। गांवों से मजदूरों का शहरों की ओर पलायन बढने के कारण खेती के समय मजदूर आसानी से उपलब्ध नहीं होते। मजबूरन, किसानों को ज्यादा दिहाड़ी देकर मजदूर बुलाने पड़ते हैं। छोटे किसानों के लिए यह खर्च और ज्यादा भारी साबित होता है। मशीनों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। ट्रैक्टर, कम्बाइन और अन्य कृषि उपकरणों का किराया पहले की तुलना में काफी महंगा हो चुका है। डीजल के बढ़ते दामों ने इस बोझ को और बढ़ा दिया है। जिन किसानों के पास कम जमीन है, उनके लिए मशीनों की लागत उत्पादन के अनुपात में और ज्यादा पड़ती है। यही वजह है कि सिर्फ गेहूं ही नहीं, बल्कि सरसों, चना और जौ जैसी फसलों की लागत भी लगातार ऊपर जा रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना शुरू किया है। यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है क्योंकि इससे किसानों को कुछ आर्थिक सहारा मिलता है लेकिन जिस तेजी से खेती की लागत बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह राहत कम ही है। कई किसानों का मानना है कि सरकार को बोनस राशि बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए ताकि उन्हें वास्तविक राहत मिल सके। केवल बोनस से समस्या का पूरा समाधान संभव नहीं है। इसके साथ ऐसी नीतियां बनाने की भी जरूरत है जो खेती की लागत कम कर सकें। असल जरूरत यह है कि राजस्थान जैसे राज्यों की खेती को उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से समझा जाए। यहां पानी सबसे महंगा संसाधन बन चुका है, इसलिए सिंचाई को सस्ता बनाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों पर ज्यादा अनुदान दिया जाना चाहिए। सोलर पंपों को तेजी से बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि किसान डीजल और महंगी बिजली के खर्च से बच सकें। गांव स्तर पर कृषि मशीन बैंक भी समय की बड़ी जरूरत बन चुके हैं। अगर अधिकाधिक किसानों को कम किराये पर ट्रैक्टर, रीपर और दूसरी मशीनें आसानी से उपलब्ध हो जाएं तो उनका खर्च काफी कम हो सकता है। छोटे किसानों के लिए तो यह व्यवस्था विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ कृषि विश्वविद्यालयों को ऐसी किस्में विकसित करने पर भी काम करना होगा जो कम पानी और कम उर्वरक में अच्छा उत्पादन दे सकें। सरकार को चाहिए कि वह डीजल, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों पर भी राहत दे। कई बार किसान फसल बोने से पहले ही कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसे में यदि इनपुट लागत कम हो तो खेती कुछ हद तक राहत दे सकती है। ग्रामीण स्तर पर खरीद केंद्र और भंडारण सुविधाएं बढ़ाने से भी किसानों का परिवहन खर्च कम किया जा सकता है। खेती पर बढ़ती लागत कम करने के लिए किसानों को भी काम करना होगा। इसके लिए किसानों को भी समय के साथ कुछ बदलाव अपनाने होंगे। परंपरागत सिंचाई की जगह कम पानी वाली तकनीकों को अपनाना होगा। सामूहिक रूप से मशीनों का उपयोग और फसल विविधीकरण भी खर्च कम करने में मदद कर सकता है। हर किसान को पूरी तरह गेहूं पर निर्भर रहने की बजाय ऐसी फसलों की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिनमें कम पानी और कम लागत की जरूरत होती है। राजस्थान के धरती पुत्र कठिन परिस्थितियों में भी देश के खाद्यान्न भंडार को भरने में बड़ा योगदान दे रहे हैं लेकिन यदि खेती की लागत इसी तरह बढ़ती रही और राहत सीमित रही तो आने वाले समय में खेती किसानों के लिए और मुश्किल हो सकती है।

नियम तोड़ने पर खिलाड़ियों-कमेंटेटर्स और टीम पर जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी

आईपीएल में रील बनाने-पोस्ट करने पर बीसीसीआई की रोक

> “एंटी-करप्शन यूनिट (एसीयू) ने आपत्ति जताई है कि कुछ वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी परिवार या दोस्तों को टीम बस में सफर करने दे रहे हैं। बीसीसीआई ने कहा कि टीम बस और होटल के प्रतिबंधित क्षेत्रों में केवल अधिकृत लोगों को ही अनुमति होगी। बोर्ड ने कहा कि यही नियम राज्यों की टी-20 लीगों में भी लागू होंगे, क्योंकि वहां भी आईपीएल के कई खिलाड़ी खेलते हैं और युवाओं के लिए गलत उदाहरण पेश करते हैं।”

नई दिल्ली, एजेंसी

खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और ब्रॉडकास्टर के लिए काम कर रहे पूर्व क्रिकेटर IPL मैच के दौरान रील नहीं बना सकेंगे और न ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाएंगे। नियम तोड़ने पर BCCI जुर्माना और कानूनी कार्रवाई कर सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL में एंटी-करप्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खिलाड़ियों, कमेंटेटर्स, उनके परिवार और ब्रॉडकास्टर्स के लिए सोशल मीडिया कंटेंट पर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। बोर्ड ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में रील या वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) ने इस सीजन में नियम उल्लंघन के कई मामले

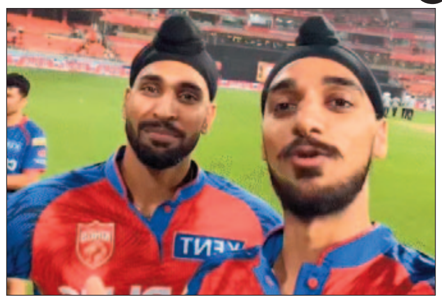

अर्शदीप सिंह IPL के रील बनाकर सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट करते हैं।

पकड़े हैं। इनमें खिलाड़ी और ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम कर रहे पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानने वालों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

बोर्ड ने खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों को IPL के दौरान फोटो और वीडियो पोस्ट करने से बचने को कहा है। पहले एक भारतीय तेज गेंदबाज को पत्नी के

डगआउट में वीडियो बना रहे पूर्व क्रिकेटर को फटकार

रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन में कुछ कमेंटेटर्स ने नियम तोड़े हैं। एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मैच के अहम पलों में डगआउट के पास फोन से वीडियो बनाते पाए गए। BCCI टीम ने तुरंत रिकॉर्डिंग रुकवाई। बोर्ड अब एक पूर्व क्रिकेटर को कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी में है, जो मैदान पर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहा था। नियम के मुताबिक, IPL की आधिकारिक ड्रेस पहनकर मैदान पर निजी कंटेंट की शूटिंग नहीं की जा सकती।

खिलाड़ियों की 'रील संस्कृति' पर बोर्ड की नजर

BCCI को चिंता है कि नई पीढ़ी के क्रिकेटर सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। एक भारतीय खिलाड़ी को टीम की यात्रा और ठहरने की जानकारी साझा करने से रोका गया है।

मीरपुर टेस्ट : बांग्लादेश ने पहले दिन 301 रन बनाए

कप्तान शांतो का शतक, मोमिनुल की फिफ्टी

नई दिल्ली, एजेंसी

मीरपुर, एजेंसी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के शतक की बदौलत बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन मजबूत शुरुआत की है। शुक्रवार को स्टंप्स तक बांग्लादेशी टीम ने पहली पारी में 4 विकेट पर 301 रन बना लिए हैं। शांतो 101 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मोमिनुल हक (91) अपने शतक से महज 9 रनों से चूक गए। शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में दिन की शुरुआत पाकिस्तान के पक्ष में रही थी, जब शान मसूद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद अब्बास ने ओपनर्स को जल्दी पवेलियन भेज दिया। एक समय बांग्लादेश ने महज 31 रनों पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद शांतो और मोमिनुल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट के लिए काफी इंतजार कराया। मीरपुर की पिच पर घास की परत को

देखते हुए दोनों टीमों ने तीन-तीन तेज गेंदबाजों को अंतिम एकादश में शामिल किया। शाहीन अफरीदी ने शुरुआत में प्रभाव डाला, लेकिन समय के साथ उनकी धार कम होती गई। मोहम्मद अब्बास और हसन अली ने भी कोशिश की, लेकिन शांतो-मोमिनुल की जोड़ी ने उनके 'प्लान' को सफल नहीं होने दिया। पाकिस्तान के लिए फिलहाल एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर सलमान आगा भी कोई बड़ा कमाल नहीं कर सके।

फिल्म ऑफर करने वाले को समझा स्टॉकर, कंगना की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थीं रामायण की सीता

34 की हुई साई पल्लवी

मुबंई, एजेंसी

इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रामायण में माता सीता के किरदार में नजर आने वालीं साई पल्लवी आज 34 साल की हो चुकी हैं। साई पल्लवी कभी एक डांस रियलिटी शो की आम सी कंटेस्टेंट हुआ करती थीं। बचपन में वो कंगना रनोट की फिल्म में बतौर जूनियर आर्टिस्ट भी नजर आईं। आज अपने हुनर और सादगी से साई पल्लवी साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर एक नजर उनके बचपन, करियर और बेहतरीन किस्सों पर- साई पल्लवी का जन्म तमिलनाडु के कोएम्बटूर में हुआ। पिता एक्साइज ऑफिसर और एक फुटबॉल प्लेयर थे और मां राधा एक डांसर थीं। बचपन में साई भी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थीं। साई महज 13 साल की उम्र में फिल्म कस्तूरी मान (2005) में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं। इसके बाद उन्होंने 2008 की तमिल फिल्म धाम धूम में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया। वो उस वक्त छठी क्लास में थीं। इस

फिल्म से कंगना रनोट ने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया था। कौन बनेगा अगला प्रभू देवा में अगर साई फाइनलिस्ट होतीं, तो उन्हें प्रभू देवा से मिलने का मौका मिलता, लेकिन सेमी फिनाले में ही शो से बाहर होने पर वो प्रभु देवा से नहीं मिल सकीं। लेकिन संयोग से सालों बाद प्रभू देवा ने उनके लिए डांस कोरियोग्राफ किया, जिसने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। साई वो डांस रियलिटी शो तो नहीं जीत सकीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई।

> मां के नक्शेकदम पर चलते साई को डांस में रुचि होने लगी। टीनएज में उन्होंने तमिल डांस शो उंगालिल यार उधुता प्रभु देवा (कौन बनेगा अगला प्रभू देवा) (2008) में हिस्सा लिया। शो के एक एपिसोड में सामंथा रुथप्रभू साई के डांस से इंप्रेस हुई थीं और जमकर तारीफ की थी।

किसिंग सीन होने पर ठुकराई विजय देवरकोंडा की फिल्म

साल 2018 में साई पल्लवी ने विजय देवरकोंडा के साथ डेब्यूटेंट डायरेक्टर भरत कम्मा के साथ फिल्म साइन की थी। इस फिल्म का पहला पोस्टर 9 मई 2018 में विजय के बर्थडे के दिन जारी हुई। हालांकि जब साई को पता चला कि उन्हें फिल्म में विजय के साथ किसिंग सीन देना होगा।

कश्मीरी पंडितों पर दिए गए बयान पर हुआ विवाद

फिल्म विराट पर्वन के प्रमोशनल इवेंट में साई के एक बयान से विवाद हो गया। दरअसल, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की तुलना गो तस्करी के आरोपियों की लिंचिंग से की है और कहा कि हिंसा कोई भी करे वह गलत है। साई ने कहा था, 'कश्मीर फाइल्स में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार दिखाया है।

अमीषा पटेल ने बॉलीवुड के ‘फेक पीआर’ पर तंज कसा

कहा- 2 फिल्में करने से कोई स्टार नहीं बनता, फिल्म गदर 3 भी कन्फर्म की

मुबंई, एजेंसी

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने बॉलीवुड में बढ़ते PR कल्चर और नई पीढ़ी के स्टार्स पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए। शनिवार को X पर अमीषा ने सबसे पहले नेगेटिव कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर्स को लेकर लिखा, 'कभी भी उन कुछ नेगेटिव यूट्यूबर्स की बातों से दुखी या परेशान मत होइए, जो हर सुबह स्टार्स की आलोचना और नेगेटिव बातें करने के लिए उठते हैं। हम स्टार्स को उनसे परेशान होने के बजाय उनके लिए खुश होना चाहिए। आखिर हमारी बुराई करके ही उनका घर चल रहा है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।' इसके बाद अमीषा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘खुद को सुपरस्टार तभी कहिए, जब आपने ऐसा काम किया हो, जिसने इतिहास बनाया हो और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हो।

दो एवरेज फिल्मों से स्टार नहीं बनतेः अमीषा

अगले ट्वीट में अमीषा ने लिखा, ‘कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने आज तक अपने करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर नहीं दी, फिर भी खुद को स्टार कहती हैं। साल में 2 एवरेज फिल्में करने और कुछ शूटिंग सेट्स पर मौजूद रहने से कोई स्टार नहीं बन जाता।

अमीषा पटेल ने पीआर मशीनरी पर साधा निशाना

PR मशीनरी को लेकर एक्ट्रेस ने लिखा, ‘कोई स्टार तभी ग्लोबल सुपरस्टार बनता है, जब वह दुनिया भर में बड़ी हिट फिल्में दे। किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना हर एक्टर के लिए अच्छी बात होती है, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन सुपरस्टार वही बनता है, जिसने बड़े हिट दिए हों।

इसलिए PR मशीनरी बंद कीजिए।’ अपनी फिल्मों का जिक्र करते हुए अमीषा ने लिखा, ‘कहो ना... प्यार है, गदरः एक प्रेम कथा और गदर 2... एक नहीं, बल्कि बतौर हीरोइन मैंने 3 सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इन तीनों फिल्मों की फुटफॉल भी सबसे ज्यादा रही।

आईपीएल 2026 में आरसीबी को किया सपोर्ट, ट्रॉफी जीतने पर बोलीं- क्यों नहीं

उर्वशी ने विराट कोहली को बताया अपना जीजू

मुबंई। बॉलीवुड अभिनेत्री Urvashi Rautela एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज और बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। आईपीएल 2026 के बीच उर्वशी ने Virat Kohli और उनकी टीम Royal Challengers Bengaluru को लेकर ऐसा बयान दिया, रौतेला ने विराट कोहली को अपना “जीजू” बताते हुए कहा कि वह आरसीबी को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। उनके इस मजेदार बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई और कई लोगों ने इसे बेहद दिलचस्प बताया। दरअसल, मिस मालिनी को दिए गए इंटरव्यू में जब उर्वशी रौतेला से पूछा गया कि वह आईपीएल 2026 में किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “हमारे तो जीजू हैं, विराट कोहली।

विराट के साथ ऐड शूट नहीं हो पाया था

इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने यह भी बताया कि विराट कोहली के साथ एक ऐड शूट करना था, लेकिन वह हो नहीं पाया था। IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में डिफेंडिंग चैंपियन RCB तीसरे स्थान पर है। टीम ने अब तक खेले गए 10 मैचों में से 6 जीते हैं और 4 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।

- 15 मई से उर्वशी की वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश 2 जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

इंस्पेक्टर अविनाश 2 में दिखेंगी उर्वशी

वर्क फ्रंट की बात करें तो उर्वशी जल्द वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश के दूसरे सीजन में नजर आएंगी। इसमें वह रणदीप हुड्डा की पत्नी पूनम मिश्रा के रोल में दिखेंगी। फिल्मों की बात करें तो उर्वशी जल्द अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल में नजर आएंगी। फिल्म 26 जून को रिलीज होगी। वहीं, उन्हें बड़े पर्दे पर आखिरी बार तेलुगु फिल्म डाकू महाराज में देखा गया था।

> आईपीएल 2026 के दौरान खिलाड़ियों और बॉलीवुड सितारों के बीच इस तरह के मजेदार कनेक्शन हमेशा फैंस का ध्यान खींचते हैं। उर्वशी रौतेला का यह बयान भी क्रिकेट और एंटरटेनमेंट दोनों दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है।

अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जारी कीं

चांद पर रहस्यमयी वस्तुएं दिखने का दावा, अंतरिक्ष यात्री बोले- बाहर आतिशबाजी जैसा नजारा

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिका में शुक्रवार को लंबे समय से चर्चा में रही UFO फाइलों की पहली खेप जारी कर दी गई। ट्रम्प प्रशासन ने सैकड़ों नए वीडियो, फोटो और पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए। इन फाइलों में सबसे ज्यादा चर्चा NASA के अपोलो मिशन से जुड़ी तस्वीरों और अंतरिक्ष यात्रियों की बातचीत को लेकर हो रही है। जारी दस्तावेजों में NASA के अपोलो 12 और अपोल 17 मिशन से जुड़ी तस्वीरें और बातचीत के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। एक तस्वीर में चांद की सतह के ऊपर आसमान में तीन रहस्यमयी बिंदु दिखाई देने का दावा किया गया है। सबसे दिलचस्प हिस्सा अपोलो 17 मिशन का ट्रांसक्रिप्ट माना जा रहा है। इसमें अंतरिक्ष यात्री उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के पास चमकती चीजें दिखने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। एक ऑपरेटर ने मिशन कंट्रोल से कहा, “कुछ चमकते कण या टुकड़े हमारे पास से गुजरते दिख रहे हैं।” इसके जवाब में

दूसरे ऑपरेटर ने कहा, “मेरी खिड़की के बाहर कई चमकती चीजें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आतिशबाजी हो रही हो।” पेंटागन की पिछली रिपोर्टों में भी कहा गया था कि कई UFO वीडियो और तस्वीरें बाद में सैन्य तकनीक या प्राकृतिक घटनाएं निकली थीं। नई UFO फाइलों में ओमान की खाड़ी के ऊपर दिखी एक रहस्यमयी वस्तु की तस्वीर सामने आई है। दावा किया गया है कि 2024 में इंफ्रारेड सेंसर ने तेज रफ्तार से उड़ती बूंद जैसी इस वस्तु को रिकॉर्ड किया था।

> “अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि शुक्रवार को जारी दस्तावेज सिर्फ शुरुआत हैं। आने वाले समय में और रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि सरकार यूएफओ मामलों में ज्यादा पारदर्शिता लाना चाहती है। कि जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोग खुद तय कर सकें कि इन घटनाओं का क्या मतलब है।

ट्रम्प ने यूएफओ से जुड़ी फाइलें जारी करने का आदेश दिया था

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ महीने पहले रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को UFO और कथित एलियन गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड जारी करने का आदेश दिया था। फाइलें जारी होने के बाद ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने सरकार की एजेंसियों को एलियन लाइफ, UFO और UAP से जुड़ी जानकारी जनता के सामने रखने को कहा था। इन फाइलों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर UFO और एलियन जीवन को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि अमेरिकी सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि उसे अब तक एलियन जीवन या एलियन टेक्नोलॉजी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है।

सैन्य विमानों के पास दिखीं रहस्यमयी वस्तुएं

पेंटागन की तरफ से जारी दस्तावेजों में 1999 के नए साल से एक दिन पहले FBI की ओर से ली गई कुछ तस्वीरें भी शामिल हैं। इनमें अमेरिकी सैन्य विमानों के पास कुछ रहस्यमयी वस्तुएं दिखाई देने का दावा किया गया है।

इसके अलावा सैन्य पायलटों की ली गई तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिनमें तेज रफ्तार से उड़ती चीजें विमानों के पास से गुजरती दिखती हैं।

यूपीआई-एटीएम के जरिए इसी महीने से निकाल सकेंगे पीएफ

7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को तुरंत पैसा मिलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी

Employees' Provident Fund Organisation यानी EPFO जल्द ही अपने करोड़ों खाताधारकों को बड़ी सुविधा देने जा रहा है। अब कर्मचारी भविष्य निधि (PF) का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। EPFO मई 2026 के अंत तक ATM और UPI के जरिए PF फंड निकालने की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद करोड़ों कर्मचारियों को अपने PF खाते से पैसा निकालने में काफी आसानी होगी। EPFO की इस पहल को “EPFO 3.0” नाम दिया गया है, जिसके तहत सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक EPFO की इस नई सुविधा का लाभ करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। खाताधारक बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए सीधे ATM या UPI के जरिए अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। अभी PF निकासी के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और कई स्तर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार इसमें लंबा समय भी लग जाता है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया काफी तेज और आसान हो जाएगी। EPFO 3.0 पहल के जरिए संगठन अपने डिजिटल सिस्टम को आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य PF सेवाओं को ज्यादा सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है।

नई व्यवस्था के तहत ऑटो-क्लेम सेटलमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। यानी कई मामलों में कर्मचारियों के दावे स्वतः मंजूर होकर राशि सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।

इसके अलावा कर्मचारी अपनी पसंद के बैंक खाते में सीधे PF राशि प्राप्त कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार यह सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और 2026 के मध्य तक इसे पूरी तरह शुरू कर दिया जाएगा।

चारबाग स्टेशन पर कार्यकर्ताओं का हंगामा, यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में नारेबाजी

ट्रेन के इंजन पर चढ़ीं पल्लवी पटेल

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने शनिवार को करीब 2 हजार कार्यकर्ताओं के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। पल्लवी यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग कर रही थीं। फिलहाल इन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। पल्लवी की पार्टी अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता दोपहर 12.30 बजे चारबाग में इकट्ठा हुए। यहां से विधानसभा कूच करने की तैयारी करने लगे। वे सब जैसे ही बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इससे गुस्साए कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन की तरफ भागे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुंचकर पल्लवी और कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर गए। ट्रैक पर खड़े इंजन पर चढ़ने लगे। देखते ही देखते पल्लवी भी इंजन पर चढ़ गईं। नारेबाजी करने लगी। करीब डेढ़ घंटे तक यानी दोपहर 2 बजे तक स्टेशन पर हंगामा होता रहा। काफी देर तक पुलिस ने

प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। बाद में प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बस में भरा और इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन कर रहे अनिल राज कोरी ने कहा- पहले हम लोगों ने बस रोकी थी। आज रेल रोकी है। अगर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज भी रोकेंगे। एयरपोर्ट पर ताला लगा देंगे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सबको वोट करता है, मगर कोई भी उसके अधिकार के लिए सामने नहीं आता। हम लोग मुकदमों से नहीं डरते, मुकदमा हमारे लिए मेडल की तरह है।

हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार और न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं कि आखिर क्यों पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है? अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सही पैरवी होनी चाहिए और सही लोगों की आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। सवर्ण समाज यूजीसी का जो विरोध कर रहा है, करता रहे। हम इसका समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे।

- पल्लवी पटेल नारेबाजी करते हुए ट्रेन के इंजन के ऊपर चढ़ गईं।
- चारबाग में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर पहुंचे थे।
- सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बड़ी-बड़ी बैरिकेडिंग की।

पल्लवी के कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है

पल्लवी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। एक-एक कर सबको बस में बैठाकर इको गार्डन भेजना शुरू कर दिया है। अचानक बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर सभी कार्यकर्ता पहुंच गए। उस समय वहां से एक इंजन धीरे-धीरे गुजर रहा था। सब उसे रुकवाकर उसके ऊपर चढ़ गए। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 दोहराने पर हमें मजबूर ना किया जाए।

"पल्लवी पटेल ने कहा- यूजीसी को हम लागू करवा कर रहेंगे। लगातार सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।"

पल्लवी चारबाग से विधानसभा की ओर जाने के दौरान पुलिस से भिड़ीं।

वोट सबको करते हैं, अधिकार के लिए कोई सामने नहीं आता

प्रदर्शन कर रहे अनिल राज कोरी ने कहा कि हम लोगों ने बस रोकी थी। आज रेल रोकी है। अगर जरूरत पड़ी तो हवाई जहाज रोकेंगे और एयरपोर्ट पर ताला लगा देंगे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सबको वोट करता है, मगर कोई भी उसके अधिकार के लिए सामने नहीं आता। आज हमने यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर अपने नेता पल्लवी पटेल के साथ रेल रोकी। यह जो दमनकारी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर हमें रोक पाएं तो रोककर दिखा दें। तब उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। बहुजन समाज जाग चुका है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 दोहराने पर हमें मजबूर ना किया जाए।

लोकतंत्र बचाने के लिए 'मल्टीलेयर इलेक्शन माफियाओं' से लड़ना होगा: अखिलेश

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए समाजवादियों को मल्टीलेयर इलेक्शन माफियाओं से लड़ना है। चुनाव में मल्टीलेयर चुनाव माफिया काम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं की साख बचाने लिए हम सबको मिलकर इनसे मुकाबला करना है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा नकारात्मक और समाज में दरारवादी पार्टी है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मांग है, जब अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी में वोट बैलेट से पड़ता है तो यहां भी वोट बैलेट से पड़े। समाजवादी पार्टी ने सबको साथ लेकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को ईवीएम से हराया है। समाजवादी पार्टी फिर भाजपा को ईवीएम से हराकर ईवीएम को हटाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि साल लगे या सदी हम ईवीएम को हटाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार स्मार्ट मीटर से जनता का जेब काट रही है। बिजली नहीं आती लेकिन स्मार्ट मीटर चलता रहता है। पता चला है कि स्मार्ट मीटर को रिमोट से भी चलाया जा सकता है।

जब स्मार्ट मीटर से बेईमानी हो रही है तो ईवीएम से क्यों नहीं हो सकती है? श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों, जिन्होंने जीवन भर खुफियागीरी की, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने सबको साथ लेकर पीडीए की ताकत से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है। अब विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को हरायेगी। श्री यादव ने कहा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने साजिश कर वोटरों का नाम डिलीट किया गया था। लोग बूथों पर पहुंचे तो उनके वोट नहीं थे। कई लोगों का वोट दूसरे बूथों पर कर दिया था। वोट मैनुपुलेट किए गये।

फास्ट न्यूज

'लखनऊ से अवैध बंग्लादेशी हटाए जाएं

लखनऊ। लखनऊ मेयर ने शनिवार सुबह शहर के कई जोन में साफ-सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जोन-4 स्थित निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी के पास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जोन-4 में ही वेंडिंग जोन पहुंचीं तो वहां गंदगी दिखीं। यह देखते ही वह गुस्से में भड़क गईं। उन्होंने मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाई। निशातगंज में बांग्लादेशियों के मामले में उन्होंने यह भी कहा कि इनको दिए गए बिजली कनेक्शन की जांच कराई जाए।

5 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने किया सुसाइड

लखनऊ। लखनऊ के विकास नगर इलाके में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पति ने कॉल करके लड़की के भाई को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है दूसरी महिला से संबंध हो जाने का लड़की विरोध करती थी। जिसके चलते उसकी हत्या कर दी। परसपुर गोंडा निवासी नायब सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बेटी साक्षी सिंह का शादी घुंघटेर बाराबंकी निवासी सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह से 25 नवंबर 2024 को की थी। शादी में लड़के वालों की मांग के अनुसार दान-दहेज दिया था।

ड्रग विभाग ने पेट दर्द-एंटी एलर्जिक दवाओं के सैंपल लिए

लखनऊ। अमीनाबाद में औषधि विभाग ने 6 मई को कई दवा कारोबारियों के यहां छापेमारी की। एंटी एलर्जिक, पेट दर्द और हड्डी रोग समेत कई दवाओं के सैंपल लिए।

अफसरों को नामी कंपनी जायडस की ऑक्सालजिन डीपी टैबलेट को लेकर शिकायत मिली थी। नकली दवाओं की आशंका पर ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्य और विवेक सिंह की टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान दवा कारोबारियों का कनेक्शन आगरा से मिला है। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने वहां पर भी छापेमारी की। दवाओं का सैंपल लिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अल्पसंख्यक छात्रों के डेंटल स्वास्थ्य पर योगी सरकार का फोकस

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के समग्र स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अग्रणी कंपनी Colgate-Palmolive के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्र तथा मदरसों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों के डेंटल स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी की के साथ कोलगेट समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मदरसा छात्रों के बीच

ओरल हाइजीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नियमित जांच की व्यवस्था करने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत कोलगेट द्वारा सीएसआर पहल के तहत प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्र तथा मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क डेंटल किट उपलब्ध कराई जाएंगी। इन किटों में टूथब्रश, टूथपेस्ट तथा अन्य आवश्यक सामग्री शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा डेंटल चेकअप कैंप भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को प्रारंभिक स्तर पर ही दांतों से संबंधित समस्याओं की पहचान और उपचार की सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री श्री दानीश आजाद अंसारी ने कहा कि "योगी सरकार का लक्ष्य केवल शैक्षिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी समुचित ध्यान रखना है। यह पहल अल्पसंख्यक छात्रों तथा मदरसा छात्रों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और उन्हें स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर करेगी।"

तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद स्वस्थ खड़ा हूं, सब इनकी कृपा

अजय राय ने दक्षिणमुखी हनुमान के दर्शन किए

- अजय राय ने सिर पर गमछा डाल रखा था। उन्होंने बजरगंबली के दर पर मत्था टेका।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को बजरंगबली के दर्शन किए। वह अस्पताल से वापसी के बाद परिवार सहित घर से सीधे हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्नी और बेटी के साथ हनुमानजी की पूजा की। बजरंगबली के सामने मत्था टेका। ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी आज बिल्कुल ठीक हूं, यह बजरंगबली का आशीर्वाद है।

'नई सरकार बंगाल में अपराध रोके'

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर बोले- सुवेंदु अधिकारी आज शपथ लेने वाले हैं। उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिल रही है। उन्हें हर तरह से अच्छा काम करना चाहिए। उनको पूरे बंगाल की जनता का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से वहां घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही है, उन सब पर तत्काल रोक लगनी चाहिए।

अजय राय ने कहा- घर से सीधे हनुमान मंदिर बजरंगबली की शरण में पहुंचा हूं। यहां पूजा-अर्चना करने के बाद प्रदेश कार्यालय जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करूंगा। भगवान ने मेरी रक्षा की। महादेव और भोले बाबा की कृपा रही कि मैं आज स्वस्थ खड़ा हूं।

अजय राय ने पूरे टाइम सर्जिकल मास्क लगाए रखा। उनके साथ पत्नी और बेटी मौजूद हैं।

'जनगणना भी एसआईआर की तरह मनगढ़ंत न हो'

उत्तर प्रदेश मैं होने वाली जनगणना पर कहा कि इसे ठीक तरह से करवाना चाहिए। इस पर SIR की तरह मनगढ़ंत काम नहीं होना चाहिए। जनगणना पूरी ईमानदारी केरलम् चुनाव को लेकर अजय राय ने कहा- विजय के पास पर्याप्त सीट हो गई है। कांग्रेस उनके के साथ है। मुझे लगता है कि TVK की सरकार बनेगी।

अखिलेश यादव बोले- गोमती रिवर फ्रंट पर लगेगी चेतक संग प्रतिमा

सपा मुख्यालय में मनाई गई महाराणा प्रताप जयंती

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। Samajwadi Party के राज्य मुख्यालय लखनऊ में शनिवार को वीरवर महाराणा प्रताप की जयंती उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री Akhilesh Yadav ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता और क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कलगीदार साफा पहने प्रतिनिधियों से खचाखच भरे Dr. Ram Manohar Lohia Auditorium में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कई राजनीतिक और सामाजिक घोषणाएं भी कीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर Gomti Riverfront पर चेतक के साथ महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिमा में सोने का भाला लगाया जाएगा और वहां एक सुंदर पार्क भी विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट विश्वस्तरीय परियोजना है और यह नदियों की सफाई का बेहतरीन मॉडल बन चुका है।

समाजवादी सरकार की योजनाओं का किया जिक्र

पूर्व मुख्यमंत्री ने समाजवादी सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि नौकरियां निष्पक्ष तरीके से दी गईं और छात्रों को बिना किसी भेदभाव के लैपटॉप बांटे गए। उन्होंने कन्या विद्याधन योजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि छात्राओं की शिक्षा में बाधा न आए, इसके लिए 30 हजार

भाजपा पर साधा निशाना

कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि भाजपा समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पहचान अलोकतांत्रिक राजनीति से जुड़ी है, माजवादी पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

मिनी मंचकिंस स्कूल फरीदी नगर में धूमधाम से मनाया गया मदर्स डे

तमसा संकेत, संवाददाता

फरीदी नगर। Mini Munchkins School में मातृ दिवस (मदर्स डे) बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं और अभिभावकों ने भाग लेकर आयोजन को यादगार बना दिया। पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां महिलाओं ने गीत-संगीत, नृत्य और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय पहुंचीं सभी महिला अतिथियों के पारंपरिक स्वागत से हुई। स्कूल प्रबंधन की ओर से महिलाओं का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौके पर गीत-संगीत, नृत्य प्रस्तुतियों और मनोरंजक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को सम्मानित और

पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक संस्था Goonj की ओर से भी विशेष सहभागिता देखने को मिली। संस्था के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोगी सामग्री एकत्रित की गई। इस पहल को उपस्थित लोगों ने काफी सराहा और इसे सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में सराहनीय कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और अभिभावकों के लिए खान-पान की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। पूरे आयोजन का संचालन विद्यालय की प्राचार्य Priyanka Pandey ने किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल बच्चों की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान देने वाली Ruchi Srivastava को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने विद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि मिनी मंचकिंस स्कूल समय-समय पर ऐसे आयोजन कर बच्चों और परिवारों को जोड़ने का कार्य कर रहा है।k

पृष्ठ 01 का शेष...

खेल मैदान अनुशासन...

मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बैंड संचालन करने वाले प्रमुख लोगों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में स्मारिका का विमोचन किया गया और देशभर से आए पुलिस एवं पैरामिलिट्री बलों के खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा में कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल जैसे खेलों का विशेष महत्व रहा है। जब हम अर्जुन का स्मरण करते हैं तो उसके साथ एकाग्रता, अनुशासन और वीरता का भाव जुड़ा होता है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहां युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में स्टेडियम नाममात्र के थे और खिलाड़ी बेहतर अवसरों के लिए भटकने को मजबूर रहते थे। अब प्रदेश सरकार खेल ढांचे को मजबूत करने के साथ खिलाड़ियों को सम्मानजनक करियर देने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि खेल कोटे के माध्यम से प्रदेश में 546 खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

सुवेंदु बंगाल में...

आज कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल की संस्कृति और भावना को पहचान मिली है। कोलकाता में BJP समर्थक शरीर पर मोदी की तस्वीर पेंट करवाकर परेड ग्राउंड पहुंचा। लोग यहां जश्न मना रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, क्योंकि वे राज्य में पहली BJP-नीत सरकार बनने से खुश हैं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के तौर पर, वे पूरे पश्चिम बंगाल का ख्याल रखेंगे और उसकी समस्याओं को हल करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में जरूर सुधार होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अस्पताल ठीक से काम करेंगे, जहां डॉक्टर मौजूद रहेंगे। स्कूल पर्याप्त शिक्षकों के साथ फिर से खुलेंगे। अभी हजारों स्कूल बंद हैं, और कई स्कूलों में सैकड़ों छात्रों के लिए सिर्फ दो शिक्षक हैं, और रिटायरमेंट के बाद कोई नई भर्ती नहीं हुई है। मेरा मानना है कि अब पश्चिम बंगाल में असली तरक्की और विकास देखने को मिलेगा। कोलकाता में सुवेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इस बीच कांथी में BJP कार्यकर्ता सुवेंदु के पैतृक आवास के बाहर जमा हो गए थे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेने के बाद, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी औपचारिक रूप से राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। यहां कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स तैनात हैं। अग्निमित्रा पाल पश्चिम बंगाल की असनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से BJP विधायक हैं। वे 2021 में पहली बार इस सीट से विधायक चुनी गई थीं। 2026 में दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने 2022 का आसनसोल लोकसभा उपचुनाव और 2024 का मेदिनीपुर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों चुनाव हार गईं। शपथ ग्रहण से पहले मंच पर PM मोदी ने पश्चिम बंगाल में BJP के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार को सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। 1952 में माखनलाल सरकार को कश्मीर में उस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जब वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वहां भारतीय तिरंगा फहराने के लिए गए थे। 98 साल की उम्र में माखनलाल सरकार आजादी के बाद के भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं। मोदी और सुवेंदु अधिकारी ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी परेड ग्राउंड में एक रोड शो कर रहे हैं। विशेष रूप से बनाए गए रथ पर पीएम और सुवेंदु साथ में मंच की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी हैं। ग्राउंड में इस वक्त करीब 1 लाख लोग मौजूद हैं।

दिल्ली में आतंकी...

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बैरिकेडिंग और वाहनों की रैंडम चेकिंग के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए आपसी तालमेल से काम कर रही हैं। बम निरोधक दस्तों, स्निफर डॉग यूनिट्स और क्विक रिएक्शन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली फायर सर्विस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों, लावारिस वस्तुओं और खड़े वाहनों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर शाम 6.52 बजे आतंकी हमला हुआ था। आतंकवादी ने चलती कार में धमका किया था। इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस धमाके के तार टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे। जिसका खुलासा जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 1 दिन पहले हरियाणा से किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर, यानी बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इकोस्पोर्ट और आई20 जैसी गाड़ियां शामिल थीं।

पंजाब के आप मंत्री...

इसके अलावा दुबई से भारत में अवैध रकम की राउंड-ट्रिपिंग के लिए इन सामानों के एक्सपोर्ट का इस्तेमाल किया। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और एक्सपोर्ट पर GST रिफंड तथा ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए दिल्ली की गैर-मौजूद फर्मों से कई फर्जी GST खरीद बिल हासिल किए गए। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और व्यक्तिगत लाभ कमाया गया। ED सोर्सेस के मुताबिक 157.12 करोड़ रुपए के फर्जी एक्सपोर्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों, डीमैट होल्डिंग्स और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। यह अटैचमेंट के आदेश 19 अप्रैल को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 की धारा 37(3) और आयकर अधिनियम की धारा 132(9B) के तहत जारी किए गए थे। जिसके तहत जांच को सही ढंग से सिरे चढ़ाने के लिए 180 दिन के लिए यह अटैचमेंट की गई है। ED ने यह कार्रवाई 17 अप्रैल को गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के परिसर, उसके प्रमुख शेयरधारक मेसर्स फाइंडोक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों और संजीव अरोड़ा, काव्या अरोड़ा, हेमंत सूद और चंद्र शेखर से जुड़े स्थानों पर की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई के बाद की। इस संबंध में सामने आए अंतरिम कुर्की आदेश के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों, कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके, फर्जी बिक्री और निर्यात को दर्शाने के लिए कथित तौर पर शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से फर्जी खरीद चालान तैयार किए। ईडी ने आरोप लगाया कि 157.12 करोड़ रुपये के कुल घोषित एक्सपोर्ट के मुकाबले, 102.50 करोड़ रुपये के लेनदेन केवल UAE स्थित दो संस्थाओं - मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम FZCO और मेसर्स ड्रैगन ग्लोबल FZCO के माध्यम से किए गए थे। ED ने आगे दावा किया है कि फोर्टबेल टेलीकॉम FZCO, मेसर्स फोर्टबेल गैजेट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी है। जिसके मालिक हेमंत सूद और चंदर शेखर हैं। इससे एजेंसी को जांच में संबंधित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से धन की राउंड-ट्रिपिंग का संदेह पैदा हुआ है, जो कि FEMA की धारा 7 और FEMA (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियम, 2015 के विनियम 9 के कथित उल्लंघन का मामला है। जब्त की गई संपत्तियों में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के कई बैंक खाते, काव्या अरोरा के डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के अलावा लुधियाना, मोहाली और गुरुग्राम में स्थित अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा ED अब विदेशी मुद्रा संबंधी कथित उल्लंघनों की चल रही जांच के तहत, ईडी संबंधित फर्मों और व्यक्तियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों की भी जांच कर रही है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकिाशत लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676